जलांश

केंद्रीय जल आयोग का मासिक सूचना - पत्र

https://cwc.gov.in/en/Jalansh

अंक.6&7

जलांश-जनवरी-फरवरी-2025
खंड-07

गतिविधियाँ

पेन्नियार नदी जल विवाद पर वार्ता समिति
महानदी बेसिन में पूर्व चेतावनी प्रणाली
सीडब्ल्यूसी और एनएचपीसी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
एनटीएफआईडब्ल्यूआरडीएम की पहली बैठक

परियोजनाएँ

पोलावरम सिंचाई परियोजना
उत्तरी कोयल परियोजना, बिहार एवं झारखण्ड
राजस्थान फीडर और सरहिंद फीडर

जलाशय निगरानी

विषय-सूची

पृष्ठ 1

परियोजनाओं के संबंध में बैठकें

पोलावरम सिंचाई परियोजना

उत्तर कोयल परियोजना

राजस्थान फीडर और सरहिंद फीडर

पृष्ठ 2

प्रशिक्षण/कार्यशाला/सम्मेलन

एनडब्ल्यूए, पुणे द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

पृष्ठ 3

साइटों/परियोजनाओं का दौरा

राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश में पोलावरम परियोजना और इसका कमान क्षेत्र

रेणुकाजी बांध परियोजना और लखवार बांध परियोजना

पृष्ठ 4

अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

देश में बाढ़ की स्थिति - दिसंबर 2024

पृष्ठ 5

अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

गोदावरी और तापी नदी बेसिन में स्थानिक बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली के संबंध में एनआरएससी के साथ बैठक

बिहार के सारण जिले में सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी परियोजना पर समीक्षा बैठक

महानदी बेसिन में बाढ़ पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी प्रणाली के संबंध में सी-डैक के साथ बैठक

पेन्नियार नदी जल विवाद पर वार्ता समिति

अंतरराज्यीय परियोजनाओं से संबंधित मुद्दे

पृष्ठ 6

अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

तीस्ता-V जलविद्युत परियोजना, सिक्किम के संबंध में सीडब्ल्यूसी और एनएचपीसी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

SHAISYS 1.0 का विकास

सिंचाई जनगणना योजना के अंतर्गत आगामी जनगणनाएं

पृष्ठ 7

अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

एकीकृत जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय कार्यबल (एनटीएफआईडब्ल्यूआरडीएम) की पहली बैठक

डी एंड आर विंग के महत्वपूर्ण मुद्दों/मामलों के संबंध में बैठक

पृष्ठ 8

अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियाँ

डब्ल्यू पी एंड पी विंग के महत्वपूर्ण मुद्दों/मामलों के संबंध में बैठक

पृष्ठ 9

जलाशय निगरानी

पृष्ठ 10

दीर्घा

पृष्ठ 11

गणतंत्र दिवस 2025

अध्यक्ष का संदेश

डॉ. मुकेश कुमार सिन्हा
अध्यक्ष, के.ज.आ.

राष्ट्रीय विकास के लिए जल मूलभूत आवश्यकता है और इसका सतत प्रबंधन सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। केंद्रीय जल आयोग (के.ज.आ) नीतियों को आकार देने, बुनियादी ढांचे को बढ़ाने एवं जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों और बढ़ती पानी की मांग को पूरा करने के लिए नवाचार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

के.ज.आ बाढ़ पूर्वानुमान, जलाशय प्रबंधन और सिंचाई तकनीकों पर ज्ञान का आदान-प्रदान करने के लिए विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करता है। ये बातचीत भारत की तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करती है और वैश्विक भागीदारी को बढ़ावा देती है।

राष्ट्रीय स्तर पर, हम भूमि अधिग्रहण के मुद्दों को हल करके और तकनीकी तत्वों को अंतिम रूप देकर, उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना और पोलावरम सिंचाई परियोजना जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं में तेजी ला रहे हैं। इसी तरह, राजस्थान और सरहिंद फीडर्स की रिलाइनिंग कई चुनौतियों के बावजूद प्रगति कर रही है।

पोलावरम, रेणुकाजी और लखवार बांधों सहित प्रमुख परियोजनाओं की साइट के दौरे ने तकनीकी बाधाओं पर काबू पाने में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की है। हमारे अभियाँत्रिकों का समर्पण सुनिश्चित करता है कि ये परियोजनाएं दीर्घकालिक लाभ देने के लिए कार्य करती रहेंगी।

के.ज.आ गोदावरी, तापी और महानदी बेसिनों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को बढ़ाने के लिए एनआरएससी और सी-डैक के साथ सहयोग कर रहा हैजिसमें बाढ़ प्रबंधन सदैव प्राथमिकता में रहता है। हमारी बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली ने पिछले मानसून में 95.53% सटीकता के साथ 10,400 से अधिक अलर्ट जारी किए, जो आपदा शमन में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर प्रकाश डालता है।

अंतर-राज्यीय जल विवादों को संबोधित करना एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। के.ज.आ पेन्नैयार नदी विवाद पर बातचीत की सुविधा प्रदान कर रहां है और विशेषज्ञ आकलन के माध्यम से अंतर-राज्य परियोजना चुनौतियों का समाधान कर रहां है। पीएमकेएसवाई के तहत, हम सिंचाई दक्षता और कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए एआईबीपी और सीएडी एंड डब्ल्यूएम कार्यक्रमों का निरंतर सहयोग करते रहते हैं।

तकनीकी प्रगति हमारे मिशन के केंद्र में है। तीस्ता-V पनबिजली परियोजना के लिए एनएचपीसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर बांध सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है। इसके अलावा, आईआईटी रुड़की के साथ SHAISYS 1.0 के विकास से भूकंपीय खतरे के आकलन में वृद्धि होगी।

क्षमता निर्माण हमारी रणनीति का अभिन्न अंग है। राष्ट्रीय जल अकादमी (एनडब्ल्यूए), पुणे, जल संसाधन इंजीनियरिंग, सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन में पेशेवरों को प्रशिक्षित करना जारी रखती है। एकीकृत जल संसाधन विकास और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय कार्य बल की पहली बैठक स्थायी जल प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

जलाशय की निगरानी कुशल भंडारण प्रबंधन सुनिश्चित करती है। 180.85 बीसीएम की लाइव भंडारण क्षमता के साथ, नियमित मूल्यांकन जल आवंटन को अनुकूलित करता है और सूखे के जोखिम को कम करता है।

आगे बढ़ते हुए, के.ज.आ जल प्रशासन में सुधार, बुनियादी ढांचे का लचीलापन बढ़ाने और सुरक्षित जल भविष्य सुनिश्चित करने के लिए नवीन तकनीकों को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं के.ज.आ के मिशन को आगे बढ़ाने में उनके अथक प्रयासों के लिए सभी अधिकारियों, इंजीनियरों और हितधारकों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। हम सब मिलकर भारत के लिए एक स्थायी जल भविष्य का निर्माण करेंगे।

परियोजनाओं के संबंध में बैठकें

पोलावरम सिंचाई परियोजना

मुख्य बांध के गैप-II में प्रस्तावित डी-वॉल के प्लास्टिक कंक्रीट मिश्रण डिजाइन के परिणामों और अन्य प्रासंगिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञों के पैनल (पीओई) और पोलावरम सिंचाई परियोजना (पीआईपी) के सभी हितधारकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेसिंग(वीसी) के माध्यम से 09.01.2025 को बैठक आयोजित की गई।इस बैठक में, 14 दिनों के मजबूती के मापदंडों के परिणामों के आधार पर प्लास्टिक कंक्रीट मिक्स के बारे में विस्तृत चर्चा की गई और मिश्रण के चयन पर विशेषज्ञों के पैनल और सीएसएमआरएस से उनके विचार देने का अनुरोध किया गया। तदनुसार, सीएसएमआरएसऔर विशेषज्ञों के पैनलके विचार प्राप्त हुए और उन्हें डिज़ाइन मिश्रण को अंतिम रूप देने के लिए केन्द्रीय जल आयोग को सूचित किया गया। इनपुट के आधार पर, कंक्रीट मिश्रण को अंतिम रूप दिया गया।

उत्तर कोयल परियोजना, बिहार और झारखंड के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए टीईसी की 42वीं बैठक

उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना (एनकेपी) के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीईसी) की 42वीं बैठक 03.01.2025 को के.ज.आ, नई दिल्ली में सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ और अध्यक्ष (टीईसी), एनकेपी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जल संसाधन विभाग, के.ज.आ मुख्यालय और क्षेत्रीय इकाइयों, बिहार, झारखंड राज्य सरकारों और डब्ल्यूएपीसीओएस के अधिकारियों ने भाग लिया।

महत्वपूर्ण एजेंडा मदों पर चर्चा हुई जैसे कि जल संसाधन विकास मंत्रालय बिहार द्वारा भूमि अधिग्रहण की स्थिति, वैपकोस द्वारा परियोजना के शेष कार्यों के विभिन्न घटकों की प्रगति, बिहार भाग (आरडी 68.37 किमी से 75.39 किमी) में आरएमसी और इसकी संरचनाओं की लाइनिंग, मरम्मत और निर्माण के कार्य के लिए निविदा की स्थिति, झारखंड की मुख्य नहर के दाएँ वितरण नेटवर्क (09 माइनर) और इसकी संरचनाओं के मृदा कार्य, मरम्मत और निर्माण के कार्य के लिए निविदा, बिहार में आरएमसी से वितरण प्रणाली के निर्माण के कार्य के लिए निविदा की स्थिति आदि।

राजस्थान फीडर और सरहिंद फीडर परियोजनाओं की रीलाइनिंग

जलशक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने 27 जनवरी, 2025 को लिखे पत्र में बताया कि इस विषय पर एक बैठक 28 जनवरी, 2025 को निर्धारित की गई है। उस बैठक में, पंजाब सरकार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव ने उपरोक्त विषय पर अतिरिक्त चर्चा बिंदु प्रदान किए। तदनुसार, 28 जनवरी, 2025 को जल संसाधन विभाग (डीओडब्ल्यूआर), नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (आरडी एंड जीआर) के सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई।

इस बैठक के दौरान एजेंडा के अनुसार निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की गई अर्थात, किसानों के विरोध से प्रभावित राजस्थान और सरहिंद फीडरों की रीलाइनिंग के शेष हिस्से के डिजाइन के मुद्दे और राजस्थान फीडर और सरहिंद फीडर परियोजना की रीलाइनिंग के शेष कार्यों को पूरा करने के लिए प्रगति और कार्य योजना की समीक्षा भी की गई।

बैठक में केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष, सदस्य (डी एंड आर) तथा केन्द्रीय जल आयोग के विभिन्न संबंधित अधिकारी उपस्थित थे तथा तदनुसार चर्चा की गई।

गिरिजा बैराज, जिला-बहराइच

प्रशिक्षण/कार्यशाला/सम्मेलन

एनडब्ल्यूए, पुणे द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रमसं.	प्रशिक्षण का नाम	अवधि	प्रतिभागियों की संख्या	उद्देश्य
1	के.ज.आ के नवनियुक्त बहुकार्य निष्पादक कर्मचारियों के लिए अनिवार्य परिचयात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम	02 सप्ताह	39	39 कैडर प्रशिक्षण
2	सामुदायिक बागवानी उत्पादन एवं विपणन संघ/डब्ल्यूयूए और सहभागी सिंचाई प्रबंधन	01 सप्ताह	14	बागवानी विभाग और जल शक्ति विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिकारियों के लिए
3	केंद्रीय जल इंजीनियरिंग सेवा (ग्रुप-ए) के वरिष्ठ टाइम स्केल (एसटीएस) अधिकारियों के लिए अनिवार्य कैडर प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमसीटीपी)	03 सप्ताह	28	कैडर प्रशिक्षण
4	जल संसाधन और उसके प्रबंधन का अवलोकन	05 दिन	58	केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) के नवनियुक्त अधिकारियों के लिए

साइटों/परियोजनाओं का दौरा

पोलावरम परियोजना और इसका कमान क्षेत्र राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश

जल संसाधन पर स्थायी समिति का अध्ययन दौरा 8 से 11 जनवरी, 2025 तक पुडुचेरी, महाबलीपुरम और राजमुंदरी में हुआ। 8-10 जनवरी, 2025 को उडुचेरी/महाबलीपुरम में और 11 जनवरी, 2025 को राजमुंदरी में के.ज.आ के अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। इस संबंध में, सदस्य डी एंड आर ने उप निदेशक, तटबंध (एनडब्ल्यू एंड एस) निदेशालय के साथ राजमुंदरी का दौरा किया।

रेणुकाजी बांध परियोजना और लखवार बांध परियोजना

लखवार बहुउद्देशीय परियोजना, उत्तराखंड और रेणुकाजी बांध परियोजना, हिमाचल प्रदेश निर्माण चरण में हैं।
लखवार बहुउद्देशीय परियोजना और रेणुकाजी बांध परियोजना से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 23-25 जनवरी 2025 तक सदस्य (डी एंड आर), के.ज.आ के नेतृत्व में सीएसएमआरएस के अधिकारियों के साथ के.ज.आ अधिकारियों का साइट दौरा किया जाएगा।

I. बाढ़ से संबंधित मामले

देश में बाढ़ की स्थिति – दिसंबर 2025

ब्रह्मपुत्र और बराक और झेलम बेसिन में नियमित बाढ़ पूर्वानुमान गतिविधि 1 मई 2024 को शुरू हुई। 1 मई से 31 दिसंबर 2024 की अवधि के दौरान, कुल 10442 (7086 लेवल + 3356 अंतर्वाह) बाढ़ पूर्वानुमान जारी किए गए, और 9967 (6790 लेवल + 3177 अंतर्वाह) पूर्वानुमान 95.45% सटीकता के साथ स्वीकार्य सीमा के भीतर थे। दिसंबर 2024 के महीने के दौरान केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से 6 रेड बुलेटिन (चरम बाढ़ की स्थिति के लिए) और 15 ऑरेंज बुलेटिन (गंभीर बाढ़ की स्थिति के लिए) जारी किए गए।

01.05.2025 से 31.12.2025 के दौरान बाढ़ की स्थिति का सारांश

चरम बाढ़ की स्थिति

छह एफएफ स्टेशन पर चरम बाढ़ की स्थिति देखी गई।

क्रम सं.	राज्य	जिला	नदी	स्टेशन	अवधि	
					से	तक
1	असम	जोरहाट	ब्रह्मपुत्र	नेमाटीघाट	30/06/2024	02/07/2024
2		सोनितपुर	जियाभराली	जिया-भराली एनटी रोड क्रॉसिंग	01/07/2024	01/07/2024
3		शिवसागर	दिखाउ	शिवसागर	02/07/2024	02/07/2024
4		डिब्रूगढ़	बुरिडीहिंग	खोवांग	02/07/2024	03/07/2024
5	बिहार	सीतामढ़ी	बागमती	ढेंग ब्रिज	28/09/2024	29/09/2024
6		मुजफ्फरपुर	बागमती	रूनीसैदपुर	29/09/2024	30/09/2024

73 बाढ़ निगरानी स्टेशन पर चरम बाढ़ की स्थिति देखी गई।

गंभीर बाढ़ की स्थिति

असम, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, त्रिपुरा, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और छत्तीसगढ़ में 91 बाढ़ नियंत्रण केन्द्रों पर गंभीर बाढ़ की स्थिति देखी गई।

आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मणिपुर, केरल, कर्नाटक, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में 134 निगरानी स्टेशनों पर गंभीर बाढ़ की स्थिति देखी गई।

सामान्य से अधिक बाढ़ की स्थिति

अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, त्रिपुरा, कर्नाटक और गुजरात के 50 बाढ़ नियंत्रण केन्द्रों पर सामान्य से अधिक बाढ़ की स्थिति देखी गई।

सीमा से अधिक अंतर्वाह वाले जलाशय

तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में 82 जलाशयों में उनकी निर्धारित सीमा से अधिक जल प्रवाह हुआ।

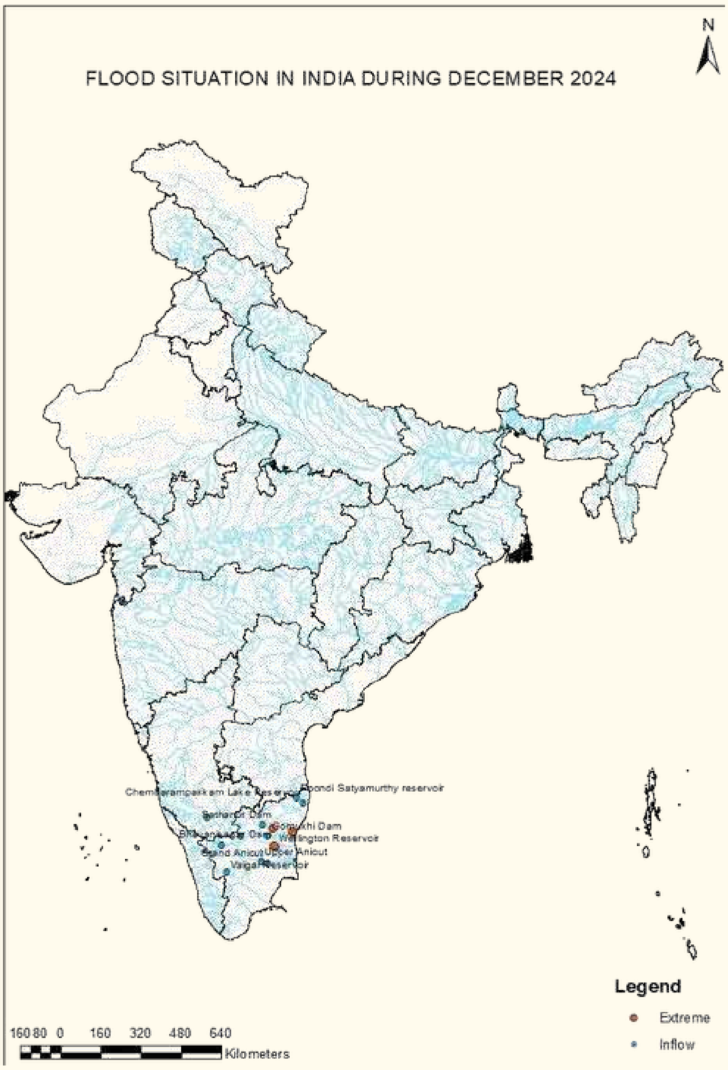

गोदावरी और तापी नदी बेसिन में स्थानिक बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली के संबंध में एनआरएससी के साथ बैठक

एनएचपी के अंतर्गत राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी), हैदराबाद द्वारा गोदावरी और तापी बेसिन में स्थानिक बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली के संबंध में कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए 09.12.2024 को समिति कक्ष, सेवा भवन, नई दिल्ली में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता के.ज.आ के अध्यक्ष श्री राकेश कुमार वर्मा ने की।

बिहार के सारण जिले में सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी परियोजना पर समीक्षा बैठक

बिहार के सारण जिले में सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी - चरण 1" की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पर चर्चा के लिए 10 जनवरी, 2025 को के.ज.आ के सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी) की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। जल संसाधन विभाग, बिहार के अधिकारियों ने परियोजना का विवरण प्रस्तुत किया।

इस परियोजना का उद्देश्य पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली को बहाल करके सिंचाई क्षमता को बढ़ाना और जल प्रबंधन में सुधार करना है। मुख्य घटकों में गाद निकालना, नहर के बुनियादी ढांचे की मरम्मत और निर्माण, नहरों को आपस में जोड़ना और SCADA(स्काडा) कार्यान्वयन शामिल हैं। समिति ने सिंचाई क्षमता के आंकड़ों को समेटने, पहले से स्वीकृत परियोजनाओं के साथ दोहराव से बचने और प्रमुख तकनीकी विवरणों को अंतिम रूप देने पर विचार-विमर्श किया।

मंजूरी में तेजी लाने के लिए, जल संसाधन विभाग, बिहार के अधिकारी दो सप्ताह के भीतर लंबित मुद्दों को हल करने के लिए के.ज.आ (मुख्यालय), नई दिल्ली का दौरा करेंगे। इसके बाद आगे के विचार के लिए अद्यतन डीपीआर और आवश्यक दस्तावेज तैयार किए जाएंगे। इस परियोजना से क्षेत्र में कृषि उत्पादकता और बाढ़ प्रबंधन में महत्वपूर्ण योगदान मिलने की उम्मीद है।

महानदी बेसिन में बाढ़ पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी प्रणाली के संबंध में सी-डैक के साथ बैठक

09.12.2024 को समिति कक्ष, सेवा भवन, आर.के.पुरम, नई दिल्ली में के.ज.आ के अध्यक्ष श्री राकेश कुमार वर्मा की अध्यक्षता में "बाढ़ की भविष्यवाणी और पूर्व चेतावनी के लिए सी-डैक के समाधान" पर हाइब्रिड मोड में बैठक आयोजित की गई। सी-डैक के वरिष्ठ सदस्य और के.ज.आ (मुख्यालय) और क्षेत्रीय कार्यालयों (एमईआरओ) के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल हुए।

सी-डैक से महानदी बेसिन के लिए विकसित डैशबोर्ड के सुधार और लॉन्च पर विस्तृत अवधारणा नोट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था, जिसमें स्थानीय समुदाय को सूचना के प्रसार के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल पर उचित जोर दिया गया था, जिसे किसानों और स्थानीय आबादी आसानी से समझ सकें।

सी-डैक को के.ज.आ के सहयोग से बाढ़ मॉडलिंग और अन्य बेसिनों में इसके आउटपुट प्रसार के लिए अपने मॉडल को स्केल करने की योजना प्रस्तुत करने के लिए भी कहा गया। अध्यक्ष ने अवधारणा नोट में उपयोगकर्ता के अनुकूल विज़ुअलाइज़ेशन, स्केलेबिलिटी, बहुभाषी सुविधा, एसएमएस और व्हाट्सएप अलर्ट आदि को उपयुक्त रूप से शुरू करने/बढ़ाने के लिए कार्य योजना पर जोर दिया।

सी-डैक से यह भी अनुरोध किया गया कि वह एपीआई के माध्यम से अन्य डैशबोर्डों, विशेष रूप से राज्य/केन्द्र सरकार की एजेंसियों के स्वामित्व वाले डैशबोर्डों में बाढ़ के परिणामों को एकीकृत करने के विकल्प का पता लगाए।

II. अंतर्राज्यीय विवाद

पेन्नियार नदी जल विवाद पर वार्ता समिति

मुख्य अभियंता, आईएमओ ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया जिसमें मुख्य रूप से तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के बीच पेन्नैयार नदी जल विवाद से जुड़े मुद्दे, पहली वार्ता समिति का संक्षिप्त विवरण, दूसरी वार्ता समिति का गठन, दूसरी वार्ता समिति द्वारा 19.09.2024 की अपनी रिपोर्ट (भाग-1) में की गई सिफारिशें और पेन्नैयार नदी बेसिन में बेसिन राज्यों द्वारा पानी की उपलब्धता और उपयोग के बारे में 30.09.2024 की अपनी रिपोर्ट (भाग-2) में समिति के निष्कर्ष शामिल थे। प्रेजेंटेशन में शामिल विषयों पर अध्यक्ष ने विस्तार से चर्चा की। बैठक में सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), सीई (आईएमओ) और आईएसएम-1 निदेशालय के अधिकारियों ने भाग लिया।

अंतरराज्यीय परियोजनाओं से संबंधित मुद्दे

बैठक में आईएमओ के मुख्य अभियंता ने अंतर-राज्यीय परियोजनाओं में शामिल अंतर-राज्यीय मुद्दों पर एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया, जो हाल ही में के.ज.आ में

मूल्यांकन के लिए प्राप्त हुए थे और अंतर-राज्यीयनदी घाटियों में स्थित परियोजनाओं में शामिल अंतर-राज्यीय पहलुओं पर भी चर्चा की। प्रेजेंटेशन के दौरान, अध्यक्ष ने प्रत्येक परियोजना पर विस्तृत चर्चा की और कुछ परियोजनाओं से संबंधित अंतर-राज्यीय मुद्दों को हल करने के लिए सुझाव दिए। बैठक में सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), सीई (आईएमओ), आईएमओ और पीएओ के अधिकारी शामिल हुए।

IV. अन्य गतिविधियाँ

तीस्ता-V जलविद्युत परियोजना, सिक्किम के संबंध में के.ज.आ और एनएचपीसी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

तीस्ता-V पावर स्टेशन सिक्किम के पूर्वी सिक्किम जिले में स्थित एक रन-ऑफ-रिवर योजना है और इसे मार्च 2008 में चालू किया गया था। इस परियोजना को पहले 9,500 क्यूमेक के पीएमएफ के लिए डिज़ाइन और निर्मित किया गया था जिसे के.ज.आ द्वारा अनुमोदित पांच स्पिलवे बे के माध्यम से पारित किया जाना था। हालाँकि, 2011 में के.ज.आ द्वारा तीस्ता बेसिन के व्यापक अध्ययन के बाद, डिज़ाइन बाढ़ को संशोधित कर 14,596 क्यूमेक कर दिया गया।

परियोजना के डिजाइन मापदंडों में निम्नलिखित परिवर्तन/संशोधन करके परियोजना के डिजाइन में बाढ़ क्षमता को बढ़ाने का प्रस्ताव है:

- बांध के ऊपर 1.5 मीटर ऊंची पैरापेट दीवार खड़ी करना
- शेष डिस्चार्ज को पास करने के लिए मौजूदा डायवर्जन सुरंगों को सुरंग स्पिलवे में बदलना

तदनुसार, एनएचपीसी द्वारा परिवर्तन ज्ञापन (एमओसी) तैयार किया गया है तथा के.ज.आ से समीक्षा परामर्शदाता की सेवाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

निदेशक, सीएमडीडी (ईएंडएनई) द्वारा सदस्य, डीएंडआर और मुख्य अभियंता, डिजाइन (ईएंडएनई) के साथ-साथ डिजाइन (ईएंडएनई), के.ज.आ के अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में 20/12/2024 को एनएचपीसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

SHAISYS 1.0 का विकास

31 दिसंबर, 2024 को SHAISYS 1.0 के विकास के तार्किक निष्कर्ष के लिए आगे के रास्ते पर चर्चा करने के लिए सेवा भवन, नई दिल्ली में उनके कक्ष में के.ज.आ के सदस्य (डी एंड आर) श्री भोपाल सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक में आईआईटी रुड़की के प्रोफेसरों की एक टीम ने भाग लिया जिसमें डॉ एम.एल. शर्मा, डॉ एन.के. गोयल और डॉ बी.आर.के. पिल्लई शामिल थे। बैठक में मुख्य अभियंता, डीएसओ और निदेशक एफई एंड एसए निदेशालय के अधिकारियों के साथ-साथ एफई एंड एसए निदेशालय भी शामिल हुए।

भूकंपीय जोखिम आकलन सूचना प्रणाली 1.0 (SHAISYS) वेबटूल में कई मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया तथा उनके पूरा होने की समयसीमा भी निर्धारित की गई, ताकि SHAISYS टूल के विकास के तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके।

सिंचाई जनगणना योजना के अंतर्गत आगामी जनगणनाएं

"सिंचाई जनगणना" योजना के तहत आगामी जनगणना की प्रगति का आकलन करने के लिए 9 दिसंबर, 2024 को जल संसाधन, आरडी और जीआर विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें एमआई (स्टेट) विंग, एनआईसी, एनआईएच और के.ज.आ के अधिकारियों ने भाग लिया।

बैठक में एलजीडी गांवों में विसंगतियों को दूर करने, एलजीडी-कोडेड गांव/शहरी वार्ड मानचित्रों को वेब मॉड्यूल में एकीकृत करने और पंचायती राज मंत्रालय के साथ एपीआई लिंकेज स्थापित करने सहित प्रमुख कार्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। विभिन्न स्तरों पर नामित मास्टर प्रशिक्षकों को निर्बाध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए संरचित प्रशिक्षण सत्र प्राप्त होंगे। जनगणना के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का नाम 'जल संसाधन जनगणना' होगा, जिसमें हिंदी संस्करण और अतिरिक्त भाषा अनुवाद के प्रावधान होंगे।

सुचारू संचालन की सुविधा के लिए, एक राज्यवार हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी, जिसमें समन्वय के लिए केंद्रीय नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। सोशल मीडिया अभियानों सहित व्यापक आउटरीच प्रयास किए जाएंगे, और माननीय जल शक्ति मंत्री द्वारा फील्डवर्क शुरू किए जाने की उम्मीद है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की तैयारियों का आकलन करने के लिए एक रैंकिंग ढांचा पेश किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, बेसिन/उप-बेसिन डेटा को जनगणना के बाद एकीकृत किया जाएगा, और 'मछली पालन' शब्दावली को 'मछली पालन/मत्स्य पालन' में अपडेट किया जाएगा। संभावित संवर्द्धन के लिए उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण (यूएटी) से फीडबैक का गंभीर रूप से मूल्यांकन किया जाएगा, और स्प्रिंग्स के लिए मोबाइल ऐप का प्रदर्शन तदनुसार निर्धारित किया जाएगा।

यह बैठक सिंचाई जनगणना के क्रियान्वयन को आगे बढ़ाने, व्यापक योजना और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई।

एकीकृत जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय कार्यबल (एनटीएफआईडब्ल्यूआरडीएम) की पहली बैठक

एकीकृत जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन (एनटीएफआईडब्ल्यूआरडीएम) के लिए राष्ट्रीय कार्य बल की पहली बैठक 21 जनवरी 2025 को सेवा भवन, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली में नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद की अध्यक्षता में आयोजित की गई। कार्य बल के औपचारिक उद्घाटन के साथ, बैठक में संदर्भ की शर्तों, संगठनात्मक ढांचे और राष्ट्रीय कार्य बल की विभिन्न प्रस्तावित गतिविधियों पर गहन विचार-विमर्श हुआ।

बैठक में अध्यक्ष (के.ज.आ), जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के अतिरिक्त सचिव, अध्यक्ष (सीजीडब्ल्यूबी), महानिदेशक (एनडब्ल्यूडीए) और संबद्ध मंत्रालयों और संगठनों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और विशेषज्ञों की भी गरिमामयी उपस्थिति रही। बेसिन योजना और प्रबंधन संगठन, के.ज.आ , कार्य बल का सचिवालय है।

डी एंड आर विंग के महत्वपूर्ण मुद्दों/ मामलों के संबंध में बैठक

अध्यक्ष, के.ज.आ की अध्यक्षता में सदस्य (डी एंड आर) और डी एंड आर विंग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ डी एंड आर विंग से संबंधित महत्वपूर्ण गतिविधियों, मामलों और मुद्दों पर चर्चा करने के साथ-साथ चल रही परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा करने के लिए 28 जनवरी, 2025 को एक बैठक आयोजित की गई थी। सदस्य (डी एंड आर) ने डी एंड आर विंग के प्रत्येक संगठन की गतिविधियों पर प्रकाश डाला, विभिन्न परियोजनाएंजो वर्तमान में डिजाइन चरण में हैं को डिजाइन करने में, सक्रिय निर्माण के तहत परियोजनाएं और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की जांचकरने में उनकी भागीदारी को रेखांकित किया । निदेशक (डी एंड आर) (सी) निदेशालय द्वारा एक प्रस्तुति दी गई, जिसमें उन्होंने पुनात्सांगछू- । और ॥, लखवाड़ एमपीपी, रेणुकाजी एमपीपी और पोलावरम परियोजनाओं सहित प्रमुख परियोजनाओं का अवलोकन प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि डिजाइन तथा परामर्श प्रक्रिया में लेआउट को अंतिम रूप देना और सीईए, परियोजना डेवलपर्स और हितधारकों के साथ बातचीत करना शामिल है, विशेष रूप से पूर्व-डीपीआर चरणों के दौरान। उन्होंने विभिन्न चुनौतियों की ओर भी ध्यान दिलाया, जिनमें अपतटीय परियोजनाओं में जल विज्ञान की जटिलता और भूमिगत निर्माण में कठिनाइयां शामिल हैं।

डब्ल्यूपी एंड पी विंग के महत्वपूर्ण मुद्दों/मामलों के बारे में बैठक

24.01.2025 को कॉन्फ्रेंस रूम, द्वितीय तल, सेवा भवन, नई दिल्ली में "डब्ल्यूपी एंड पी विंग में संभाले जा रहे महत्वपूर्ण मुद्दों/मामलों" पर चर्चा करने के लिए के.ज.आ के अध्यक्ष की अध्यक्षता में डब्ल्यूपी एंड पी विंग के सभी मुख्य अभियंताओं के साथ एक बैठक आयोजित की गई। डब्ल्यूपी एंड पी विंग के तहत विभिन्न संगठनों द्वारा किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक के दौरान चल रही परियोजनाओं को सुव्यवस्थित करने और प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने पर जोर दिया गया। कार्रवाई योग्य बिंदुओं की पहचान की गई और डब्ल्यूपी एंड पी विंग के तहत कार्यों की निरंतर प्रगति और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारियां सौंपी गईं। बैठक के कार्यवृत्त बाद में डब्ल्यूपी एंड पी समन्वय निदेशालय द्वारा जारी किए गए।

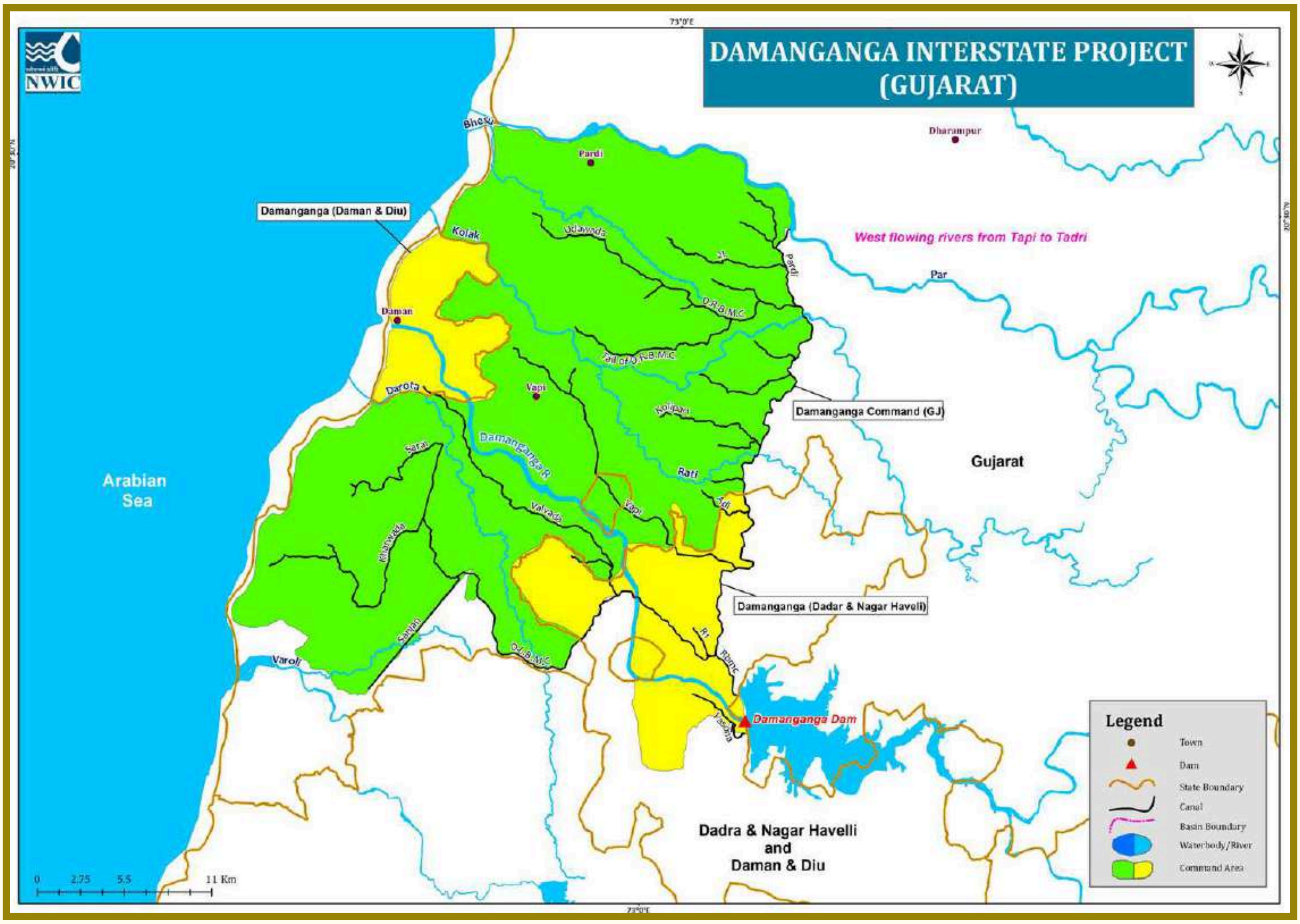

जलाशय निगरानी

केंद्रीय जल आयोग देश के 155 जलाशयों की जल संग्रहण स्थिति की निगरानी कर रहा है तथा प्रत्येक गुरुवार को साप्ताहिक बुलेटिन जारी कर रहा है। इन जलाशयों में से 20 जलाशय जलविद्युत परियोजनाओं के हैं, जिनकी कुल जल संग्रहण क्षमता 35.299 बीसीएम है। 155 जलाशयों की कुल जल संग्रहण क्षमता 180.852 बीसीएम है, जो देश में अनुमानित 257.812 बीसीएम जल संग्रहण क्षमता का लगभग 70.15% है।

दिनांक 30.01.2025 के जलाशय संग्रहण बुलेटिन के अनुसार, इन जलाशयों में उपलब्ध सक्रिय संग्रहण 114.914 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल सक्रिय संग्रहण क्षमता का 64% है। हालाँकि, पिछले वर्ष इसी अवधि के लिए इन जलाशयों में उपलब्ध सक्रिय संग्रहण 94.739 बीसीएम था और पिछले 10 वर्षों का औसत सक्रिय संग्रहण 98.786 बीसीएम था। इस प्रकार, 30.01.2025 के बुलेटिन के अनुसार 155 जलाशयों में उपलब्ध सक्रिय संग्रहण पिछले वर्ष की इसी अवधि के सक्रिय संग्रहण का 121% और पिछले दस वर्षों के औसत सक्रिय संग्रहण का 116% है।

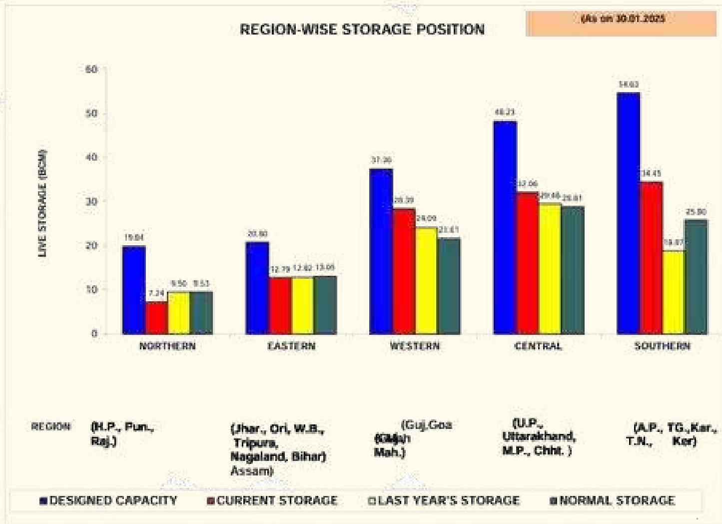

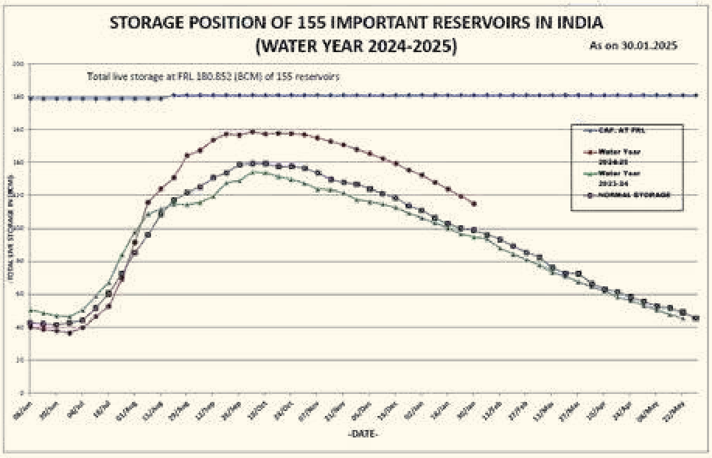

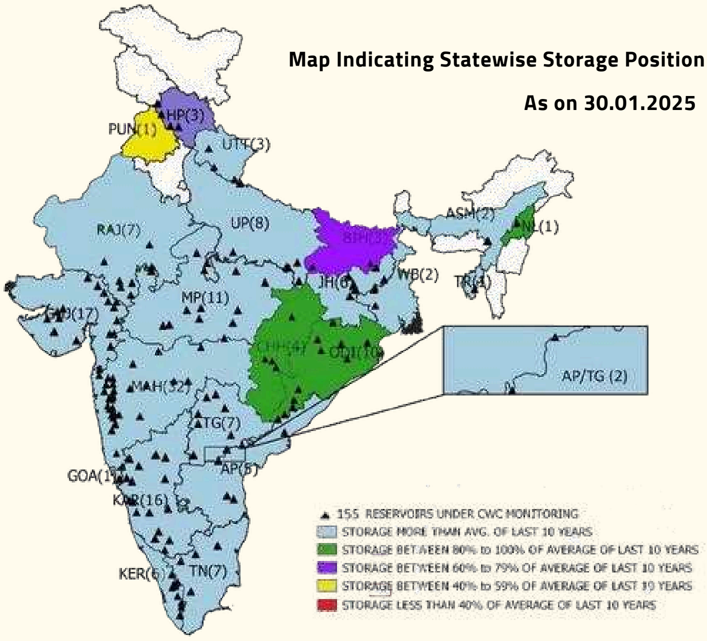

Map Indicating Statewise Storage Position
As on 30.01.2025

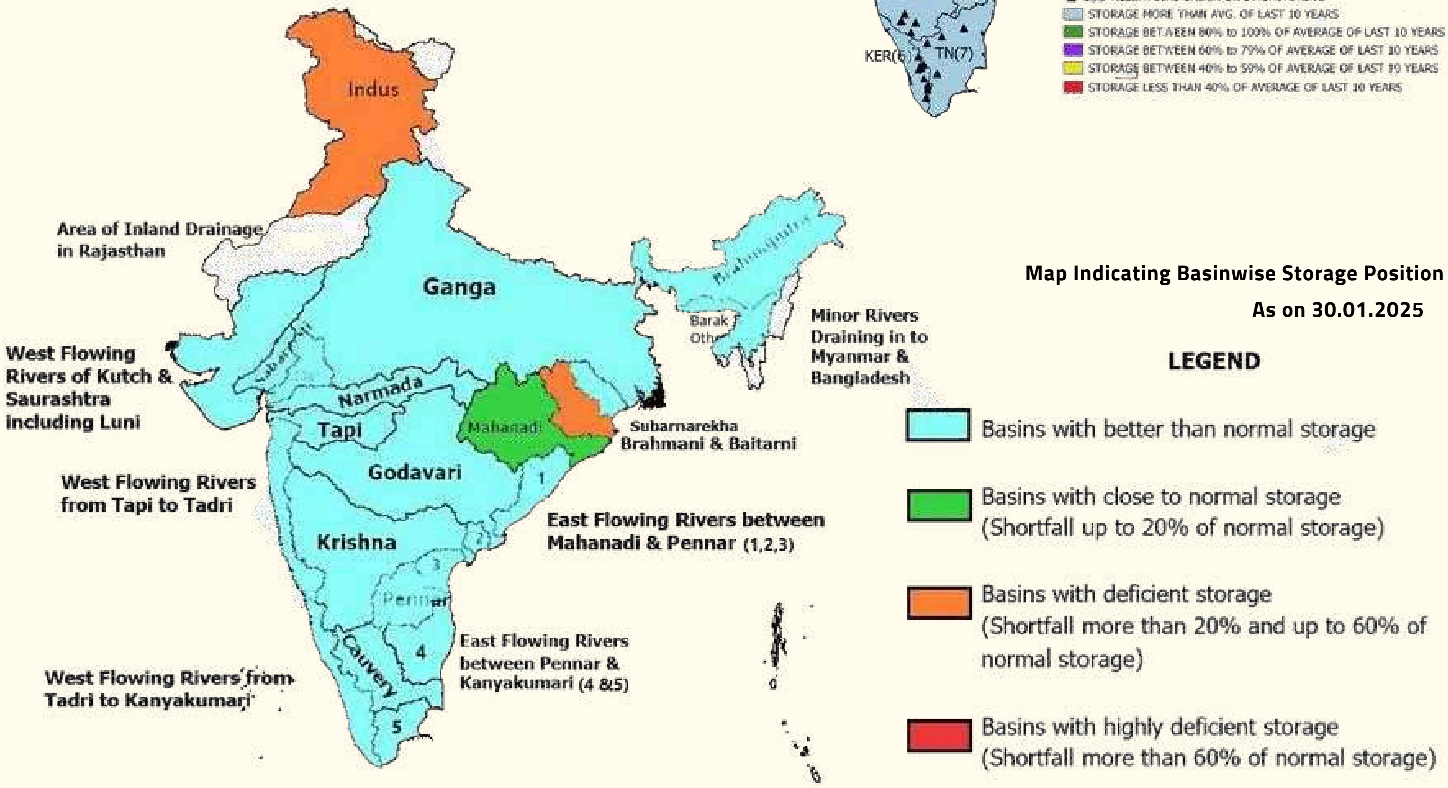

दीर्घा

आईडब्ल्यूटी मुद्दों के लिए तटस्थ विशेषज्ञ कार्यवाही से संबंधित एक बैठक 28 जनवरी 2025 को सदस्य (डी एंड आर), सीडब्ल्यूसी की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई थी। चर्चा में निर्माण कार्यक्रम और तटस्थ विशेषज्ञ के साथ साझा किए गए चित्रों को अंतिम रूप दिया गया।

सदस्य (डी एंड आर), सीडब्ल्यूसी ने 22 जनवरी 2025 को हाइड्रोलॉजिकल अध्ययन संगठन में कार्य की स्थिति की समीक्षा की। मुख्य अभियंता, एचएसओ और संबंधित निदेशालयों के निदेशकों ने परामर्श परियोजनाओं की स्थिति और लंबित परियोजनाओं की समस्याओं के बारे में बताया।

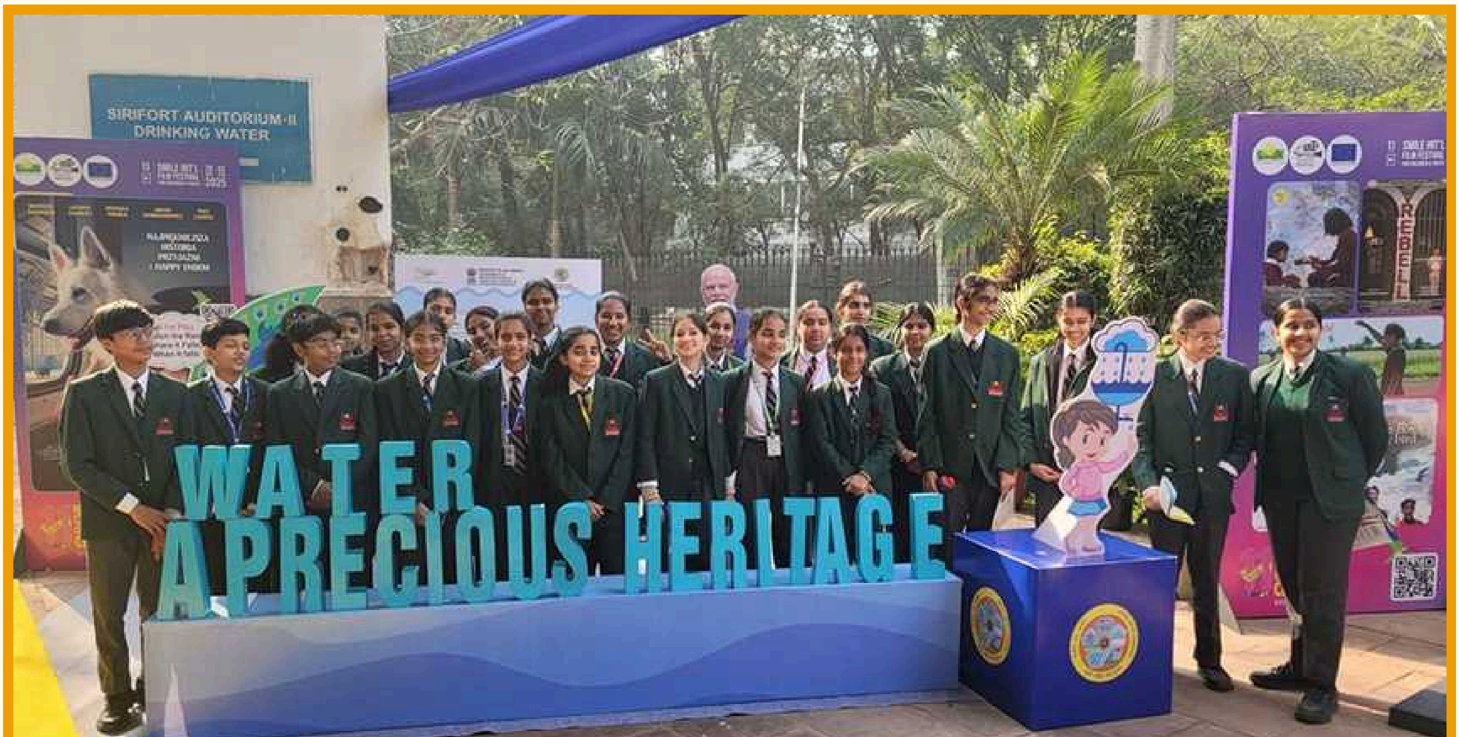

बच्चों और युवाओं के लिए स्माइल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (SIFFCY) में 28-30 जनवरी 2025 तक जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन विभाग की ओर से केंद्रीय जल आयोग ने भाग लिया। सिनेमा महोत्सव में जलशक्ति मंत्रालय की कई लघु फिल्में और वृत्तचित्र दिखाए गए। जलशक्ति मंत्रालय की लघु एनिमेटेड फिल्म "यमुना की कहानी" ने वृत्तचित्र श्रेणी में जूरी पुरस्कार जीता।

गणतंत्र दिवस 2025

सीडब्ल्यूसी मुख्यालय, नई दिल्ली

राष्ट्रीय जल अकादमी (एनडब्ल्यूए), सीडब्ल्यूसी, पुणे

केंद्रीय जल आयोग

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का एक सम्बद्ध कार्यालय

संपादक मंडल

- श्री भूपिंदर सिंह , मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) - मुख्य संपादक
- श्री योगेश पैथंकर, मुख्य अभियंता(पीएमओ) - सदस्य
- श्री राकेश टोटेजा, निदेशक(नदी प्रबंध समन्वय) - सदस्य
- श्री मनोज कुमार, निदेशक (टीसी)- सदस्य
- श्री सुनीलकुमार -II, निदेशक(डब्ल्यूपीएंडपी–सी)- सदस्य
- श्री श्री शेखरेन्दु झा, निदेशक (ज.प्र.अभि.) – सदस्य
- श्री रवि रंजन , निदेशक (डीएण्डआर सम.) - सदस्य
- श्री कैलाश के. लाखे, उप निदेशक(ज.प्र.अभि.)-सदस्य सचिव
- अनुवाद - श्रीमति मीना कुमारी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

अभिकल्प एवं प्रकाशन

जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय
केन्द्रीय जल आयोग

द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110 066
ई-मेल: media-cwc@gov.in